



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]
No. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2008/माघ 24, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2008/MAGHA 24, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 1

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 85(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68घ की उप-धारा (1) और धारा 68छ के साथ पठित तत्त्वर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(अ), दिनांक 16 मार्च, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त दोनों अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारियों/प्रशासकों में अधिकारिता के निम्नलिखित क्षेत्रों को आर्बिट्रिट करती है :-

क्र.सं.	सक्षम प्राधिकारी के नाम	अधिकारिता
1	2	3
1.	सक्षम प्राधिकारी, कोलकाता	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र।
2.	सक्षम प्राधिकारी, चेन्नई	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र।
3.	सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र।
4.	सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई	गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य और दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र।

टिप्पण : सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता का क्षेत्र निरुद्ध व्यक्ति या उस व्यक्ति के पते या निवास पर आधारित होगा जिसके विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के अधीन निरोध आदेश जारी किया गया है या जिसको आरोपित किया गया है। यदि एक से अधिक पते या निवास स्थान हों तो उस सक्षम प्राधिकारी को अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता में प्रायोजक या अन्वेषक अभिकरण अवस्थित है। ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनका भारत में कोई पता या निवास स्थान नहीं है, उस सक्षम प्राधिकारी को अधिकारिता होगी जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में उस व्यक्ति को निरोध किया जाता है/आरोपित किया जाता है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के समतुल्य किसी अपराध के लिए भारत के बाहर दौड़िक अधिकारिता रखने वाले किसी

सक्षम न्यायालय द्वारा पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सिद्धोष किए गए व्यक्ति की बाबत वह सक्षम प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर होगी, सक्षम प्राधिकारी होगा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति अवस्थित है या वह सक्षम प्राधिकारी होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

[फा. सं. एच. 13011/1/2007-सीए]

एस. के. त्यागी, निदेशक (एचक्यूआरएस.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION NO. 1

New Delhi, the 13th February, 2008

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) read with sub-section (1) of Section 68D and Section 68G of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and in supersession of the notification number G.S.R. 189(E), dated the 16th March, 2001, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government is pleased to allocate the following areas of jurisdiction among the Competent Authorities or Administrators for the purposes of the said two Acts :—

Sl. No.	Name of Competent Authority	Jurisdiction
1	2	3
1.	Competent Authority, Kolkata	States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, West Bengal and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
2.	Competent Authority, Chennai	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tarnilnadu and Union Territories of Puducherry and Lakshdweep.
3.	Competent Authority, New Delhi	States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union Territories of Chandigarh and National Capital Territory of Delhi.
4.	Competent Authority, Mumbai	States of Gujarat, Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.

Note: The area of jurisdiction of the Competent Authorities shall be on the basis of the address or residence of the detinue or the person against whom detention order has been issued or the person who has been charged under the relevant Acts. If there is more than one address or place of residence, the Competent Authority in whose jurisdiction the sponsoring or investigating agency is located, shall have the jurisdiction. In case of persons who do not have any address or place of residence in India, the Competent Authority in whose area of jurisdiction the person is detained or charged, shall have the jurisdiction. In respect of a person convicted by a competent court of criminal jurisdiction outside India for an offence similar to an offence punishable under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 with imprisonment for a term of five years or more, the Competent Authority who shall have jurisdiction shall be the competent authority in whose area of jurisdiction the illegally acquired property is located or the Competent Authority, who has been authorised by the Central Government by an order.

[F. No. H-13011/1/2007-CA]

S. K. TYAGI, Director (Hqrs.)